News सिटी चीफ
वर्ष-15, अंक-145
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

बिहार सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार
CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM
बिहार, शुक्रवार 30 अगस्त 2024

आज का विचार

अच्छे विचार और अच्छी सोच से आचरण भी अच्छा बनता है।

सुप्रीम कोर्ट के जज के घर चोरी

नीट पेपर लिक मामले में की थी सुनवाई ; बड़े भाई भी रह चुके हैं गृह सचिव

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ । पटना, बिहार में पिछले कुछ दिनों से आपराधिक घटनाओं में तो इजाफे की बात कहीं ही जा रही है। लेकिन, चोरी की घटना में भी तेजी देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि चोर आम तो आम खास लोगों के घर में भी बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार ही जा रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है। अब एक ऐसा ही मामला राजधानी पटना से निकल कर सामने आया है। जहां सुप्रीम कोर्ट के जज

के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इन्होंने ही हाल में नीट पेपर लिक मामले की सुनवाई की थी। जानकारी के मुताबिक, पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में चोरों ने सुप्रीम कोर्ट के जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जज अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। पटना आवास पर घर की देखरेख के लिए एक गार्ड मो. मुस्तकीम है, जो चोरी के वक्त अपने घर चला गया था। अगली सुबह केयर टेकर जब जज के आवास पर पहुंचा तो चोरी की जानकारी मिली। यह घटना पाटलिपुत्र कॉलोनी में मकान संख्या 133 में ये वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि, यह आवास जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यह उनका निजी आवास है। सूचना मिलते ही पाटलिपुत्र थाने की पुलिस के साथ पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस फिलहाल पाटलिपुत्र थाने में चोरी का मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज कई बड़े -बड़े मामले में सुनवाई कर चुके हैं जिसमें एक मामला हाल ही का नीट पेपर लिक केस भी है। उधर, यह भी जानकारी सामने आयी है कि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बड़े भाई अफजल अमानुल्लाह बिहार के गृह सचिव रह चुके हैं। अफजल भी दिल्ली में ही रहते हैं। इनकी पत्नी परवीन अमानुल्लाह बिहार सरकार में मंत्री थी, उनकी मौत हो चुकी है। इस मामले में पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के DSP दिनेश कुमार पांडे ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के घर चोरी की सूचना मिली है। केस दर्ज कर लिया गया है। घर में किसी के नहीं रहने के कारण चोरी कितने की हुई है इसका आंकलन नहीं हो पाया है। CCTV फुटेज को देखा गया है। उस इलाके के कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। चोर चिन्हित भी किया गया है। बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बिहार के डीजीपी भट्टी की विदाई

CISF के डीजी बनाये गये, छवि कड़क थी लेकिन कोई कमाल नहीं दिखा पाये

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ । पटना, बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी की विदाई हो गयी है. केंद्र सरकार ने आज उन्हें सीआईएसएफ का डीजी बनाने का आदेश जारी कर दिया है. दिसंबर 2022 में बिहार के डीजीपी का कार्यभार संभालने वाले भट्टी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी. राज्य सरकार ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दे दी थी. आज उनकी पोस्टिंग कर दी गयी. केंद्र सरकार की ओर से भट्टी की नयी पोस्टिंग को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसके मुताबिक 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आर.एस. भट्टी को सीआईएसएफ का डीजी बनाने की जानकारी दी गयी है. भट्टी 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे. यानि वहां उनका कार्यकाल 13 महीनों का होगा. पहले से तय थी विदाई आरएस भट्टी ने दिसंबर 2022 में बिहार के डीजीपी का कार्यभार संभाला था. उनकी छवि कड़क अधिकारी की मानी जाती रही है. लेकिन बिहार का डीजीपी बनने के बाद वे कोई कमाल नहीं दिखा पाये. बिहार के लॉ एंड आर्डर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे. ऐसी लगातार घटनायें होती रहीं, जिससे सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठते रहे. आखिरकार वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिये गये. पहली दफे डीजीपी ने पद छोड़ा बिहार के इतिहास में संभवतः ये पहला वाकया है जब डीजीपी ने अपना पद छोड़ कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का फैसला लिया है. भट्टी का कार्यकाल अभी एक साल और बचा था. लेकिन बीच में ही उन्होंने सीआईएसएफ में जाने का फैसला ले लिया. सीआईएसएफ का डीजी ऐसा अहम पद नहीं होता जिसके लिए किसी राज्य का डीजीपी अपनी कुर्सी छोड़ दे. **दबाव में थे भट्टी** पुलिस मुख्यालय के सूत्रों की मानें तो डीजीपी के पद पर रहते हुए राजविंदर सिंह भट्टी दबाव में थे. वे पुलिस को ठीक करने के लिए फ्री हैंड चाहते थे. लेकिन पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों तक में ट्रांसफर पोस्टिंग में डीजीपी की नहीं चल रही थी. एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी ही नहीं बल्कि डीएसपी तक की पोस्टिंग सीएम आवास से की जा रही थी. ऐसे में भट्टी अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार आरोप लगा रहे थे कि पुलिस में डीजीपी की चल नहीं रही है. चढावा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है. डीजीपी ने अपने पसंद के अधिकारियों की फील्ड में तैनाती की लिस्ट तैयार की थी लेकिन सरकार ने उसका नोटिस नहीं लिया. तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम के चमचे-बेलचे ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं.

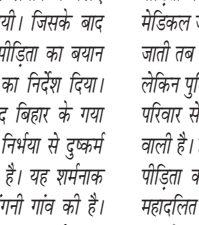

बिहार के गया में महादलित लड़की के साथ गांव के दो युवकों ने किया गंदा काम

पकड़े गये आरोपी को पुलिस ने बाइज्जत छोड़ा

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ । *गया, बिहार के गया में कोलकाता जैसी घटना हुई है। जहां नाबालिग युवती के साथ गांव के ही दो युवकों ने गंदा काम किया। जब रेप करते आरोपियों को घरवालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया तब पुलिस ने दोनों को बाइज्जत छोड़ दिया। ना मेडिकल कराया ना बयान दर्ज कराया आखिर ऐसा करने के पीछे पुलिस की मंशा क्या है? थानेदार के रवैय्ये को भाप पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंच गयी। जिसके बाद उन्होंने गुरपा थानाध्यक्ष को पीड़िता का बयान लेकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोलकाता की घटना के बाद बिहार के गया जिले में एक और नाबालिग निर्भया से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। यह शर्मनाक घटना गुरुपा थाना क्षेत्र के टेंगनी गांव की है। जहां जन्माष्टमी के दिन यह घटना हुई। जब महादलित परिवार के घटवार समाज की नाबालिग लड़की अपने घर के अंदर सोई हुई थी तभी अचानक गांव के दो युवक उसे घर में अकेला देख घुस गया और बारी-बारी से रेप किया। पीड़िता ने बताया कि गांव के ही रंजीत कुमार और सचिन कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके चिल्लाने के बाद घर के दूसरी तरफ सोई उसकी माँ और चाची ने रंजीत को पकड़ लिया लेकिन सचिन भागने में सफल रहा लेकिन मामला इतने पर नहीं रुका। इस मामले में गुरपा पुलिस की संवेदनहीनता भी सामने आई। परिजनों ने पकड़े गए रंजीत कुमार को पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन जब पीड़िता पुलिस के साथ थाने जा रही थी तब पीड़िता और उसके परिजनों को पुलिस ने कहकर डरा दिया कि थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराओगी तो न्यूज पेपर और मोबाइल पर आ जाएगा। जिसके बाद गहन जांच की जाएगी। इस दौरान काफी फजीहत में पड़ जाओगी। पुलिस थाने में*

ले जाकर दूसरी कहानी बनाकर आवेदन लिखवा दिया और दोनों आरोपी को छोड़ दिया गया। जबकि पीड़िता चीख चीख कर बता रही थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। गुरपा पुलिस ने ना नहीं पीड़िता का 164 का बयान कराया और ना ही मेडिकल जांच ही कराया। मेडिकल जांच करायी जाती तब पीड़िता के आरोपों की पुष्टि हो जाती। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पीड़िता गरीब परिवार से आती है और जंगली क्षेत्र की रहने वाली है। हाई प्रोफाइल वाले मामले में देर सवेर पीड़िता को न्याय मिल जाती है लेकिन इस महादलित नाबालिग निर्भया को इंसाफ मिल भी पाएगी या नहीं या फिर उसकी चीख जंगलों में ही गुम हो जाएगा कहना मुश्किल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता रेप कांड के बाद कहा था कि महिलाओं के अपराधों को क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस वारदात से पीड़िता काफी सदमे में है। आज वो एसएसपी आशीष भारती से मिलने पहुंची थी जहां न्याय की गुहार लगायी। एसएसपी आशीष भारती ने गुरपा थानाध्यक्ष को फोन किया और पीड़िता का बयान लेकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि थानेदार साहब एसएसपी का बात सुनते हैं या फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं।

आज ही के दिन तरियानी छपरा में 10 वीर सपूतों ने एक साथ दी थी जान की आहुति

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ । शिवहर, देश के दीवानों को जलियांवाला बाग की तरह दूसरा तरियानी छपरा में उन वीर सपूतों को गोलियों की बौछारों से नींद में सुला दी थी अंग्रेजी पुलिसों ने शिवहर देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिला शिवहर के वीर सपूतों ने भी देश की रक्षा करने को लेकर तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनी जान गंवाकर मातृभूमि की रक्षा की है । तरियानी छपरा पंचायत के 10 वीर सपूतों ने 30 अगस्त 1942 को देश की आजादी में अपना जान न्योछावर कर दिया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरे देश में जलियांवाला बाग के बाद दूसरा तरियानी छपरा में उन वीर सपूतों के स्मारक के नाम आता है। अंग्रेज की गोलियों के शिकार हुए वीर सपूतों का दर्जा सबसे ऊपर लिया जाता है, जहां आज भी स्कूलों की किताबों में देखने व पढ़ने को मिल जाएगा। हालांकि वैसे पवित्र स्थल के निर्माण को लेकर आज भी प्रशासनिक उदासीनता एवं जनप्रतिनिधि की अपेक्षा बरकरार है। 30 अगस्त 1942 को स्वतंत्रता आंदोलन के दीवाने तरियानी छपरा पंचायत के शहीद 65 वर्षीय नवजद सिंह, 30 वर्ष के भूषण सिंह, 45 वर्षीय शहिद जय मंगल सिंह ,32 वर्षीय सुखदेव सिंह, 30 वर्षीय सुंदर राम, 40 वर्षीय बुधन महतो, 35 वर्षीय बंसीदास, 50 वर्षीय परसन साह, 45 वर्षीय छठू साह, 55 वर्षीय बलदेव सिंह सुमित 10 वीर

सपूतों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी। स्थानीय मुखिया अर्पणा सिंह ने बताया है कि उन में अंग्रेजों की हुकूमत को टक्कर देते हुए शहीद श्याम नंदन सिंह ने बक्सर जेल में राजनीतिक बंदी की मांग हेतु आवरण अनशन पर बैठे रहे, उन्होंने 22वें दिन देश के लिए शहीद हो गए। गौरतलब हो कि तरियानी छपरा चौक पर वर्ष 2016 के 27 नवंबर को महात्मा गांधी जी की मूर्ति अनावरण के दौरान जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह सभा को संबोधित करते हुए अपने निजी कोष से सैकड़ो लोगों के बीच शहीद स्मारक स्थल निर्माण करने की घोषणा की थी, तकरीबन 20 लाख की लागत से चार दीवारी निर्माण कार्य कराया गया।

तत्कालीन सांसद रमा देवी ने भी स्मारक स्थल पहुंच पत थ चार दिवारी के निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रुपए दिए थे। पंचायत संस्था से मुखिया द्वारा मनरेगा से मिट्टी भराई का कार्य किया गया तथा तत्कालीन डीएम राजकुमार ने भी शहीद स्मारक को शहीद पार्क के रूप में परिवर्तन किया जाने की घोषणा की थी और मॉडल पार्क बनाए जाने को कहा था लेकिन बात कागज पर ही सिमट के रह गई। स्थानीय ग्राम वासियों ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा कर श्रमदान करते हुए वीर सपूतों की याद में कुछ हद तक शहीद स्मारक स्थल का निर्माण कराया। आज शहीद दिवस पर मुखिया अर्पणा सिंह एवं सामाजिक कार्यकर्ता नितेश सिंह महाराज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन है जहां वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी।

बढ़ाई गई मोहन भागवत की सुरक्षा

अब मोदी और अमित शाह की तरह मिलेगी हाई क्लास सिक्योरिटी

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ । पटना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन्हें अब उस तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिस तरह की सुरक्षा देश के अंदर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को हासिल है। मोहन भागवत को अब अधिक सुरक्षा मुहैया करवाया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा के स्तर को काफी बढ़ा दिया गया है। उनकी सुरक्षा कैटेगरी के जेड प्ल से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (एएसएल) कर दिया गया है। लिहाजा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी की जाएगी। इसको लेकर हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा समीक्षा की गई थी। जिसमें पाया गया कि गैर भाजपा दलों के द्वारा शासित राज्यों में ढिलाई बरती गई है। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। मालूम हो कि, भागवत की जेड-प्लस सुरक्षा में सीआईएसएफ से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी और गार्ड

शामिल थे। ऐसा कहा जा रहा है कि मोहन भागवत को लेकर लगातार बढ़ती हुई धमकी और विभिन्न एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद गृह मंत्रालय ने मोहन भागवत को एएसएल सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के रूप में घोषित किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक तौर पर अपग्रेड के बारे में सूचित कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि, एएसएल के तहत सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों जैसी स्थानीय एजेंसियों की भागीदारी अनिवार्य है। इसमें बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे शामिल है। हेलीकॉप्टर यात्रा की अनुमति केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टरों में दी जाएगी।

बिहार में कोई अच्छा अधिकारी रहना नहीं चाहता

बोले तेजस्वी..IPS को दबाकर रखना चाहते हैं IAS, ट्रांसफर-पोस्टिंग में होती है नीलामी

पटना, दिसंबर 2022 में बिहार के ष्ठत्रक्कका कार्यभार संभालने वाले राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी और 28 अगस्त को उनकी पोस्टिंग की गयी। बिहार से उनकी विदाई हो गयी है। केंद्र सरकार ने उन्हें ष्टढ्ढस्स्न का ष्ठत्र बनाने का आदेश जारी कर दिया। राजविंदर सिंह भट्टी की बिहार से विदाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिहार में कोई अच्छा अधिकारी रहना नहीं चाहता है।उन्होंने कहा कि अभी तो डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी का कार्यकाल बाकी था। किसी राज्य का डीजीपी ष्टढ्ढस्स्न के डीजी से कई गुणा ताकतवर होता है। हर किसी का सपना होता है कि वो स्टेट का डीजीपी बने। राजविंदर सिंह भट्टी पहले भी केंद्र में थे। उनको काम करना था इसलिए बिहार आए लेकिन बिहार में जो माहौल उनको देखने को मिला विवश होकर उन्हें फैसला लेना पड़ गया। तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाया कि कुछ आईएएस है जो आईपीएस को दबाकर रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार के राज्य में आईएएस और आईपीएस की ट्रांसफर-पोस्टिंग जो होती है उसे पूरी तरीके से नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज्यादा नीलामी में भागीदार होता है उसी को अच्छी पोस्टिंग नीतीश के राज में मिलती है। खुला दिल निलामी होता है यह सब कोई जानते है। इसलिए अच्छे अधिकारी यहां रहना नहीं चाहते हैं। बिहार में इसी तरह का माहौल बना दिया गया है। वही बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी बलात्कार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए लेकिन जाकर क्या मार्केट में तोड़फोड़ करियेगा? क्या उसका साथ आप लोग दे रहे है? जो बाजार में खुल्ले डकैती की जा रही तो उन लोगों के साथ क्या बीजेपी खड़ी है? तेजस्वी ने आगे कहा कि पूरे बंगाल में बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। शांति का माहौल भंग कर रहे हैं लोगों को उकसाने का काम लगातार कर रहे है। लेकिन लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों में रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है उस पर चुप्पी क्यों बीजेपी साधे हुए है।

फिर किसी खेल की तैयारी में हैं नीतीश

संसदीय कमेटी की बैठक में JD ने कांग्रेस और TMC का दिया साथ

पटना, पलटी मारने के लिए चर्चित नीतीश कुमार के दिमाग में क्या फिर कुछ चल रहा है. आज दिल्ली में संसदीय कमेटी की एक बैठक में जेडीयू के सांसद ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया. इससे पहले भी केसी त्यागी से लेकर जेडीयू के कई दूसरे नेता बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ बोल चुके हैं.

जेडीयू ने बीजेपी को घेरा दिल्ली में आज संसदीय कमेटी की बैठक में जेडीयू ने कांग्रेस और टीएमसी की मांग का पुरजोर समर्थन किया. दरअसल, गुरुवार को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति की बैठक थी. इस बैठक में डीएमके और कांग्रेस के सांसद ने जातीय जनगणना की मांग उठायी. ममता बनर्जी की टीएमसी ने इसका समर्थन किया. फिर जेडीयू के सांसद भी विपक्षी पार्टियों का साथ देने के लिए सामने आ गये.

जातीय जनगणना पर रार इस कमेटी की बैठक में जेडीयू ने कहा कि में बैठक में जाति आधारित जनगणना पर चर्चा की जाये. डीएमके के सदस्य टीआर बालू ने समिति की पहली बैठक में यह मुद्दा उठाया. भाजपा सांसद गणेश सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर चाहते थे कि समिति की बैठक में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना पर चर्चा हो. टीएमसी के सदस्य कल्याण बनर्जी ने उनका समर्थन किया. इसके बाद जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव भी उनके समर्थन में आ गये. गिरधारी यादव ने कहा कि समिति जाति आधारित जनगणना पर चर्चा करे और उसके लिए पहल करने की सिफारिश करे. टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने मांग की कि समिति %जाति आधारित जनगणना% कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखे. बता दें कि बीजेपी ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लीयर नहीं किया है. लेकिन सरकार में सहयोगी पार्टी जेडीयू अब बीजेपी पर खुलकर दबाव बनाने लगी है. पहले भी जेडीयू के नेताओं ने मीडिया में बयान देकर केंद्र सरकार से मांग किया है कि वह देश भर में जाति आधारित जनगणना कराये. जेडीयू कह रही है कि उसने बिहार में जातिवार जनगणना कराई थी और उसके आंकड़े भी जारी किए थे. उसके बाद बिहार में आरक्षण को बढ़ाने का विधेयक भी पास किया गया था.

बीजेपी-जेडीयू में टकराव बढा मामला सिर्फ जातीय जनगणना का नहीं है. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी ने चार दिन पहले इजराइल को लेकर भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ बयान दिया था. केसी त्यागी ने कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों के नेताओं के साथ बयान पर साइन कर केंद्र सरकार से ये मांग की है कि वह इजराइल से हथियारों का लेन-

देन बंद कर दें और फिलिस्तीन का समर्थन करे. वहीं, केंद्र के नये वक्फ बिल पर भी जेडीयू के नेता बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ बयान दे रहे हैं.